



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 654]  
No. 654]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 12, 2009/कार्तिक 21, 1931  
NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 12, 2009/KARTIKA 21, 1931

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 नवम्बर, 2009

सा.का.नि. 819 (अ).—भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 4 के उप-नियम (1) और (2) के साथ पठित अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, जम्मू और कश्मीर सरकार के परामर्श से भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) विनियमावली, 1955 में आगे और संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन विनियमों का नाम भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) तीसरा संशोधन विनियमावली, 2009 होगा।

(2) ये विनियम शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) विनियमावली, 1955 की अनुसूची में "जम्मू और कश्मीर" शीर्षक और उसके नीचे आने वाली प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

जम्मू और कश्मीर

राज्य सरकार के अधीन वरिष्ठ इयूटी पद	75 तैनाती के लिए न्यूनतम अवधि (वर्ष में)
मुख्य सचिव	1 -
वित्त आयुक्त, राजस्व	1 2
प्रधान सचिव	6 2
अध्यक्ष, जम्मू और कश्मीर विशेष अधिकरण	1 2
मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव	1 2
राज्यपाल के प्रधान सचिव	1 2
प्रधान स्थानिक आयुक्त	1 2
सरकार के आयुक्त और सचिव	11 2
मंडलीय आयुक्त	2 2
परिवहन आयुक्त	1 2
मुख्य निर्वाचन अधिकारी	1 2
आयुक्त, वाणिज्यिक कर	1 2
उत्पाद शुल्क आयुक्त	1 2
पंजीयक, सहकारिता सोसायटीज	1 2
उपायुक्त	22 2
निदेशक, उद्योग एवं वाणिज्य	2 2
निदेशक, उपभोक्ता कार्य एवं सार्वजनिक वितरण	2 2

सरकार के सचिव/विशेष सचिव/अपर सचिव	6	2
श्रम आयुक्त	1	2
पुनर्वास आयुक्त	1	2
अपर उपायुक्त	4	2
अपर जिला विकास आयुक्त	7	2
1. कुल वरिष्ठ ड्यूटी पद	75	
2. सी.डी.आर. उपर्युक्त मद 1 के 40% से अधिक नहीं	30	
3. एस.डी.आर. उपर्युक्त मद 1 के 25% से अधिक नहीं	18	
4. टी.आर. उपर्युक्त मद 1 के 3.5% से अधिक नहीं	02	
5. एल.आर. और कनिष्ठ पद रिजर्व उपर्युक्त मद 1 के 16.5% से अधिक नहीं	12	
6. भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 9 के अधीन पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पद उपर्युक्त मद 1, 2, 3 और 4 के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं	62	
7. सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पद (1 + 2 + 3 + 4 + 5 - 6)	75	

कुल प्राधिकृत पद-संख्या 137

[फा. सं. 11031/07/2008-अ.भा.से. 11(क)]

हरीश सी. राय, डेस्क अधिकारी

टिप्पणी 1 : इस अधिसूचना के जारी होने से पूर्व, जम्मू और कश्मीर संवर्ग की कुल प्राधिकृत पद संख्या 112 थी।

टिप्पणी 2 : मुख्य विनियम दिनांक 22 अक्टूबर, 1955 की सं. का. नि. आ. 3350 द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे। तत्पश्चात्, भारतीय प्रशासनिक सेवा के जम्मू और कश्मीर संवर्ग के संदर्भ में निम्नलिखित सा.का.नि. संख्याओं तथा तिथियों द्वारा ये संशोधित किए गए :

क्र.सं.	सा.का.नि.सं.	तिथि
1.	429(अ)	17-10-1974
2.	97	8-2-1986
3.	505	18-8-1990
4.	333	4-7-1994
5.	739(अ)	31-12-1997
6.	362(अ)	17-5-2007
7.	188(अ)	24-3-2009

## MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 12th November, 2009

G.S.R. 819 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the All India Services Act, 1951, (LXI of 1951) read with sub-rules (1) and (2) of Rule 4 of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954, the Central Government, in consultation with the Government of Jammu and Kashmir hereby makes the following regulations further to amend the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1955, namely :—

1. (1) These regulations may be called the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Third Amendment Regulations, 2009.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1955, under the heading "JAMMU AND KASHMIR" for the entries occurring there under, the following shall be substituted namely :—

### JAMMU AND KASHMIR

Senior Duty Posts under the State Government	75	Minimum tenure for posting (in years)
Chief Secretary	1	—
Financial Commissioner Revenue	1	2
Principal Secretary	6	2
Chairman, J&K Special Tribunal	1	2
Principal Secretary to Chief Minister	1	2
Principal Secretary to Governor	1	2
Principal Resident Commissioner	1	2
Commissioner and Secretary to Government	11	2
Divisional Commissioner	2	2
Transport Commissioner	1	2
Chief Electoral Officer	1	2
Commissioner, Commercial Taxes	1	2
Excise Commissioner	1	2
Registrar Cooperative Societies	1	2
Deputy Commissioners	22	2
Director Industries and Commerce	2	2
Director Consumer Affairs and Public Distribution	2	2
Secretaries/Special Secretaries/Additional Secretaries to Government	6	2

Labour Commissioner	1	2
Settlement Commissioner	1	2
Additional Deputy Commissioners	4	2
Additional District Development Commissioners	7	2
1. Total Senior Duty Posts	75	
2. Central Deputation Reserve not exceeding 40% of item 1 above	30	
3. State Deputation Reserve not exceeding 25% of item 1 above	18	
4. Training Reserve not exceeding 3.5% of item 1 above	02	
5. Leave Reserve and Junior Posts Reserve not exceeding 16.5% of item 1 above	12	
6. Posts to be filled by promotion under Rule 9 of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954 not exceeding 50% of items 1, 2, 3, and 4	62	
7. Posts to be filled up by Direct Recruitment (items 1 + 2 + 3 + 4 + 5 - 6)	75	
<b>Total Authorized strength</b>	<b>137</b>	

[F. No. 11031/07/2008-AIS-IIA]  
HARISH C. RAI, Desk Officer

**Note 1 :** Prior to the issue of this notification, the Total Authorized Strength of Jammu & Kashmir IAS Cadre was 112.

**Note 2 :** The Principal Regulations were published in the Gazette of India vide No. SRO 3350, dated 22-10-1955. Subsequently, they were amended in respect of the Jammu and Kashmir Cadre of Indian Administrative Service vide following G.S.R. numbers and dates :—

Sl. No.	G.S.R. Nos.	Date
1.	429(E)	17-10-1974
2.	97	8-2-1986
3.	505	18-8-1990
4.	333	4-7-1994
5.	739(E)	31-12-1997
6.	362(E)	17-5-2007
7.	188(E)	24-3-2009

#### अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 नवम्बर, 2009

सा.का.नि. 820 (अ).—अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, जम्मू और कश्मीर सरकार के परामर्श से भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियमावली,

2007 में आगे और संशोधन करने के लिए, एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (i) इन नियमों का नाम भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) चौथा संशोधन नियमावली, 2009 है।

(ii) ये नियम शासकीय राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियमावली, 2007 में,

“अनुसूची II-क में, राज्य सरकारों के अधीन भारतीय प्रशासनिक सेवा में समय वेतनमान के रूप के वेतन वाले पदों” में, प्रथम कॉलम में “जम्मू और कश्मीर” के नीचे आने वाली प्रविष्टियाँ और दूसरे कॉलम में तदनुसूची प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

#### जम्मू और कश्मीर

मुख्य सचिव	रु. 80,000 (नियत)
वित्त आयुक्त, राजस्व	रु. 80,000 (नियत)
प्रधान सचिव	एचएजी वेतनमान 67,000-79,000 (3% की दर से वार्षिक वेतनवृद्धि)
अध्यक्ष, जम्मू और कश्मीर विशेष अधिकरण	एचएजी वेतनमान 67,000-79,000 (3% की दर से वार्षिक वेतनवृद्धि)
मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव	एचएजी वेतनमान 67,000-79,000 (3% की दर से वार्षिक वेतनवृद्धि)
राज्यपाल के प्रधान सचिव	एचएजी वेतनमान 67,000-79,000 (3% की दर से वार्षिक वेतनवृद्धि)
प्रधान स्थानिक आयुक्त	एचएजी वेतनमान 67,000-79,000 (3% की दर से वार्षिक वेतनवृद्धि)
सरकार के आयुक्त और सचिव	वेतन बैंड-4+ग्रेड वेतन 10,000 रु.
मंडलीय आयुक्त	वेतन बैंड-4+ग्रेड वेतन 10,000 रु.
परिवहन आयुक्त	वेतन बैंड-4+ग्रेड वेतन 10,000 रु.
मुख्य निर्वाचन अधिकारी	वेतन बैंड-4+ग्रेड वेतन 10,000 रु.
आयुक्त वाणिज्यिक कर	वेतन बैंड-4+ग्रेड वेतन 10,000 रु.
उत्पाद शुल्क आयुक्त	वेतन बैंड-4+ग्रेड वेतन 10,000 रु.
पंजीयक, सहकारिता सोसायटीज	वेतन बैंड-4+ग्रेड वेतन 10,000 रु.

(ख) “अनुसूची II-भाग ख” में वेतन के अतिरिक्त विशेष वेतन वाले पदों सहित राज्य सरकारों के अधीन भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ वेतनमान वाले पदों में “जम्मू और कश्मीर” के तहत आने वाली प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

उपायुक्त

निदेशक, उद्योग एवं वाणिज्य

निदेशक, उपभोक्ता कार्य एवं सार्वजनिक वितरण

Chairman, J&K Special Tribunal HAG Scale—67,000—79,000  
(annual increment @ 3%)

सरकार के सचिव/विशेष सचिव/अपर सचिव

Principal Secretary to Chief Minister HAG Scale—67,000—79,000  
(annual increment @ 3%)

श्रम आयुक्त

पुनर्वास आयुक्त

Principal Secretary to Governor HAG Scale—67,000—79,000  
(annual increment @ 3%)

अपर उपायुक्त

अपर जिला विकास आयुक्त

Principal Resident Commissioner HAG Scale—67,000—79,000  
(annual increment @ 3%)

[फा. सं. 11031/07/2008-अ.भा.से. (II)ख]

हरीश सी. राय, डेस्क अधिकारी

Commissioner and Secretary to Government PB-4 + GP Rs. 10,000

**टिप्पणी :** मुख्य नियम दिनांक 20-3-2008 की सं. सा.का.नि. 213(अ) द्वारा भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे और बाद में, दिनांक 19-9-2008 की सं. सा.का.नि. 665(अ) तथा दिनांक 15-4-2009 की सं. सा.का.नि. 123(अ) द्वारा संशोधित किए गए।

Divisional Commissioner PB-4 + GP Rs. 10,000

Transport Commissioner PB-4 + GP Rs. 10,000

Chief Electoral Officer PB-4 + GP Rs. 10,000

Commissioner, Commercial Taxes PB-4 + GP Rs. 10,000

Excise Commissioner PB-4 + GP Rs. 10,000

Registrar Cooperative Societies PB-4 + GP Rs. 10,000

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 12th November, 2009

**G.S.R. 820(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the All India Services Act, 1951, (61 of 1951) the Central Government, in consultation with the Government of Jammu and Kashmir hereby makes the following rules further to amend the Indian Administrative Service (Pay) Rules, 2007, namely:—

1. (i) These rules may be called the Indian Administrative Service (Pay) Fourth Amendment Rules, 2009.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Indian Administrative Service (Pay) Rules, 2007:—

In “Schedule II-A posts carrying pay above the time scale of pay of the Indian Administrative Service under the State Governments”, in the table, for the entry “JAMMU AND KASHMIR” occurring in the first column and corresponding entries in the second column, the following shall be substituted namely:—

**JAMMU AND KASHMIR**

Chief Secretary	Rs. 80,000 (fixed)
Financial Commissioner, Revenue	Rs. 80,000 (fixed)
Principal Secretary	HAG Scale—67,000—79,000 (annual increment @ 3%)

(b) In “Schedule II-Part B” Posts carrying pay in the senior scale of the Indian Administrative Service under the State Governments including posts carrying special pay in addition to pay, for the entries occurring under ‘Jammu and Kashmir’, the following shall be substituted, namely:—

Deputy Commissioners

Director, Industries and Commerce

Director, Consumer Affairs and Public Distribution  
Secretaries/Special Secretaries/  
Additional Secretaries to Government

Labour Commissioner

Settlement Commissioner

Additional Deputy Commissioners

Additional District Development Commissioners

[F. No. 11031/07/2008-AIS-II-(B)]

HARISH C. RAI, Desk Officer

**Note :** The Principal Rules were published in the Extraordinary Gazette of India vide No. G.S.R. 213(E), dated 20-3-2008 and subsequently were amended vide No. G.S.R. 665(E), dated 19-9-2008 and 123(E), dated 15-4-2009.